मुख्यमंत्री डॉ. यादव बलराम कृषि महोत्सव छतरपुर में वर्चुअल रूप से जुड़े

अन्नादाताओं को दी जा रही हैं आवश्यक सुविधाएं : मोहन

सच प्रतिनिधि || भोपाल

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि धरती पुत्र परिश्रम से फसल उगाते हैं, जो सभी को उपलब्ध होता है। अन्नदाता किसानों की समस्याओं को दूर कर उन्हें सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव नई दिल्ली प्रवास के दौरान शनिवार को बलराम कृषि महोत्सव छतरपुर में वर्चुअल रूप से जुड़कर संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने प्रगतिशील किसानों से संवाद भी किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि बुंदेलखंड हीरों की धरती है। यहां की जमीन में हीरा निकलता है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने जिले में होने वाली पिपरमेंट की खेती का भी जिक्र किया। साथ ही फर्नीचर की क्वालिटी को बेहतर बताया। छतरपुर जिले के किसानों को रबी सीजन की फसलों की नवीनतम तकनीक, उन्नत कृषि पद्धतियों एवं आधुनिक कृषि संसाधनों की जानकारी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से हुए बलराम कृषि महोत्सव के रूप में आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ जनप्रतिनिधियों ने दीप जलाकर किया। छतरपुर में वन एवं पर्यावरण राज्यमंत्री श्री दिलीप अहिरवार, प्रशासक अपेक्स बैंक डॉ. महेन्द्र सिंह यादव, प्रशासक सहकारिता श्री के.पी. सिंह, विधायक राजनगर श्री अरविंद पटेरिया उपस्थित थे।

केन-बेतवा परियोजना से बुंदेलखंड के किसानों को मिलेगा सिंचाई का बड़ा लाभ

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा प्रारंभ की गई केन-बेतवा लिंक परियोजना की सराहना करते हुए कहा कि इस महत्वाकांक्षी परियोजना से बुंदेलखंड सहित संबंधित क्षेत्रों के किसानों को सिंचाई का भरपूर लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि सिंचाई की सुविधा बढ़ने से कृषि क्षेत्र को नई गति मिलेगी और किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।

मुख्यमंत्री ने आल्हा-ऊदल के प्रसंग का उल्लेख करते हुए बुंदेलखंड की वीरता और गौरवशाली परंपरा का वर्णन किया। उन्होंने किसानों एवं उपस्थित लोगों से सामाजिक आयोजनों में अनावश्यक खर्च कम करने तथा सामूहिक विवाह को बढ़ावा देने की अपील की।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव को किसानों ने बताए कृषि क्षेत्र के नवाचार

मुख्यमंत्री डॉ. यादव को किसानों ने कृषि क्षेत्र के नवाचारों की जानकारी दी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने छतरपुर जिले के प्रगतिशील किसान सलीम खान से संवाद किया। सलीम ने जैविक एवं प्राकृतिक खेती के साथ होलेस्टिक फार्मिंग एवं औषधीय फसल उत्पादन एवं कृषि के साथ अन्य कृषकों को प्राकृतिक खेती के लिए प्रोत्साहित करने के संबंध में मुख्यमंत्री डॉ. यादव को जानकारी दी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव को बिजावर निवासी कृषक सौरभ भटनागर ने बताया कि वे जैविक एवं प्राकृतिक खेती के साथ फल और सब्जी उत्पादन कार्यक्रम तथा होलेस्टिक फार्मिंग (मुर्गी पालन, मछली पालन, बतख पालन) करते हैं। जनजाति समाज की श्रीमती हब्बीबाई ग्राम सलैया ने बताया कि उनके द्वारा कोदो, कुटकी, रागी, बाजरा, ज्वार एवं अन्य लघु धान्य फसलों का उत्पादन करते हुए प्रोसेसिंग के साथ बाजार में बेचा जाता है। ग्राम हतना निवासी श्री अनिल यादव ने बताया कि उन्होंने कस्टम हायरिंग केन्द्र की स्थापना की। ट्रैक्टर सहित कुल 6 यंत्र खरीदे। गत वर्ष अन्य किसानों को किराए पर यंत्र उपलब्ध करवाने से लगभग 5.50 लाख तक मुनाफा प्राप्त हुआ है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने किसान श्रीमती तुलसा कुशवाहा निवासी लखनगुवां से भी संवाद किया। श्रीमती तुलसा ने बताया कि जैविक एवं प्राकृतिक खेती के साथ फसल और सब्जी उत्पादन, मुर्गी पालन, मछली पालन, बतख पालन आदि कर रहीं हैं जो उन्हें मुनाफा दे रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने विभिन्न जनप्रतिनिधियों से भी संवाद किया।

कार्यक्रम में वन एवं पर्यावरण राज्यमंत्री श्री दिलीप अहिरवार सहित अन्य जनप्रतिनिधियों ने जिले के 10 प्रगतिशील किसानों को प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया। साथ ही प्रावीण्य सूची में आए कृषकों के बच्चों को भी सम्मानित किया गया।

बलराम कृषि महोत्सव में कृषि वैज्ञानिक एवं विषय विशेषज्ञ किसानों को रबी मौसम की प्रमुख फसलों की उन्नत किस्मों, नवीनतम कृषि तकनीक, बेहतर कृषि पद्धतियों, फसल प्रबंधन तथा समसामयिक कृषि विषयों की जानकारी दी गई। साथ ही किसानों को आधुनिक तकनीक अपनाकर उत्पादन और कृषि आय बढ़ाने के संबंध में भी मार्गदर्शन दिया गया।

बलराम कृषि महोत्सव में किसानों के लिए विभिन्न विभागों एवं संस्थाओं द्वारा प्रदर्शनी और स्टॉल लगाए गए। इसमें नवीनतम बीज किस्मों, उन्नत कृषि यंत्रों, उर्वरकों के उपयोग एवं ई-विकास के माध्यम से उर्वरक वितरण सहित कृषि से संबंधित विभिन्न सुविधाओं की किसानों को जानकारी दी गई। इसके साथ ही उद्यानिकी, पशुपालन एवं कृषि अभियांत्रिकी विभाग द्वारा भी स्टॉल लगाकर निजी कृषि विक्रेताओं द्वारा कृषि उपयोगी सामग्री एवं तकनीकों से संबंधित प्रदर्शनी के माध्यम से किसानों को जानकारी उपलब्ध करवाई गई।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने नई दिल्ली में केंद्रीय श्रम एवं रोज़गार मंत्री मनसुख मांडविया से सौजन्य भेंट की। इस अवसरपर मध्यप्रदेश के विकास, रोज़गार सृजन, युवाओं के कौशल विकास तथा प्रदेश में रोज़गार के नए अवसरों के विस्तार से जुड़े विभिन्न विषयों पर सार्थक चर्चा हुई।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने नई दिल्ली में केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह से भेंट की। इस दौरान मध्यप्रदेश में वस्त्र एवं टेक्सटाइल क्षेत्र के विस्तार, निवेश की संभावनाओं, औद्योगिक विकास तथा रोज़गार सृजन से जुड़े विभिन्न विषयों पर सार्थक चर्चा हुई।

परिजनों के कंधों पर नदी पार कर स्कूल पहुंच रहे मासूम पांच साल में दो बार भूमि पूजन, फिर भी नहीं बना डैम

सच संवाददाता || डिंडोरी

बीते दिनों एक तस्वीर वायरल हुई थी जिसमें छात्राएं स्कूल तक पहुंचने के लिए स्टॉप डैम को फांदकर अपना सफर तय कर रही थीं। इस घटना का हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया राज्य सरकार से जवाब मांग लिया। एक ऐसी ही तस्वीर डिंडोरी से सामने आई है। यहां स्कूल तक पहुंचने के लिए छात्राओं को अपने अभिभावकों पीठ पर सवार होकर नदी पार करते हुए देखा जा सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि लंबे समय से मांग करने के बावजूद तुरार नदी पर पुल नहीं बन पा रहा है। पुल के लिए दो बार भूमि पूजन हुआ, राज्य सरकार ने पैसा भी पास कर दिया लेकिन स्थानीय प्रशासन अब इस पुल का निर्माण नहीं करवा सका है।

कर्रोजया ब्लॉक के टाफिया टोला में तुड़ार नदी पर स्टॉप डैम निर्माण के लिए दो बार भूमि पूजन हुआ, लेकिन 5 साल बाद भी काम शुरू नहीं हो पाया है। सेनगुड़ा ग्राम पंचायत के सरपंच देव सिंह नाटी ने बताया हमारे गांव में तुरार नाम की एक नदी बहती है। इस नदी से होकर एक रास्ता जाता है। नदी के एक तरफ कुतरी, मोहगांव, बर टोला, धड़कन टोला, टिकरा टोला, देवरी, बरबसपुर के अलावा कई और गांव हैं। और यही एकमात्र रास्ता इन गांवों को मुख्य बाजार अस्पताल से जोड़ता है।

बरसात के दिनों में इस नदी में कमर तक पानी आ जाता है। ऐसी स्थिति में लोग तेज बहाव वाले पानी में ही नदी पार करते हैं। सबसे ज्यादा दिक्कत स्कूली बच्चों को होती है। बच्चों को परिजन अपनी गोद में बैठाकर या पीठ पर लादकर नदी पर करवाते हैं। कई बार नदी की धार तेज आ जाती है तो लोग बह भी जाते हैं। अगर नदी में पानी ज्यादा रहता है तो बच्चे फंस जाते हैं घर नहीं पहुंच पाते।

इसी गांव के रहने वाले मथुरा प्रसाद ने बताया सबसे ज्यादा समस्या मरीजों को होती है। मरीज को नदी पार करवाने के लिए चार लोग पहले खटिया को कंधे पर रखते हैं और उसको किसी तरह से नदी पार करवाते हैं।ऐसा नहीं है कि इस समस्या के बारे में किसी को पता नहीं है। नदी किनारे ही एक शिलालेख लगा है जो 2021 का है। उस समय नदी के ऊपर एक चेक डैम और उसी के ऊपर से रास्ता बनाने के लिए प्रस्ताव रखा गया था। योजना भी बन गई थी भूमि पूजन भी हो गया था। इस योजना की लागत लगभग 30.99 लाख रुपये आंकी गई थी लेकिन काम शुरू नहीं हुआ।देव सिंह बताते हैं कि जब उन्होंने इसके बार में अधिकारियों से पूछा तो उनका कहना था कि इस जगह पर रेत ज्यादा है, इसलिए इतने कम पैसे में यह निर्माण कार्य नहीं हो पाएगा। इसके बाद स्वीकृत राशि बढ़वाने के लिए 19 अप्रैल 2022 को फिर उसी काम के लिए 72 लाख 99 हजार रुपये की स्वीकृति मिली। 24जुलाई 2023 में विधायक ओमकार मरकाम, शहपुरा विधायक ओमप्रकाश धुर्वे, जिला पंचायत अध्यक्ष रुदेश परस्ते ने गांव में जाकर भूमिपूजन किया। लेकिन इस भूमि पूजन को भी 3 साल बीत गए हैं लेकिन अब तक काम शुरू नहीं हो सका है।

जिला पंचायत सीईओ दिव्यांशु चौधरी ने बताया इस संबंध में फाइल चेक करवा रहा हूं। जैसे ही बारिश खत्म होती है इस काम को शुरू करवाया जाएगा। स्थानीय लोगों का कहना है कि ओंकार सिंह मरकाम इस क्षेत्र से विधायक हैं। उनका कहना है कि हमें इस इलाके से वोट नहीं मिलता इसलिए हमारी इस पुल को लेकर दिलचस्पी नहीं है। वहीं सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते का कहना है कि वह कई बार अधिकारियों से कह चुके हैं लेकिन अधिकारी उनकी सुन नहीं रहे हैं।

मंडला के बिछिया विकासखंड के अतारिया गांव के लोगों के लिए सड़क आज भी एक सपना बनी हुई है। आजादी के इतने साल बाद भी गांव तक पहुंचने के लिए पक्की सड़क नहीं है। पगडंडी और नालों से होकर नन्हे बच्चों और शिक्षकों को स्कूल पहुंचना होता है। बरसात के दिनों में यही नाला इन बच्चों के लिए बड़ी चुनौती बन जाता है। नाला उफान पर हो तो बच्चों के कदम ठिठक जाते हैं। अतारिया गांव के सरकारी स्कूल के सहायक शिक्षक अमृत सिंगोर ने बताया कि अंजनिया से स्कूल का पहुंच मार्ग लगभग 5 किलोमीटर लंबा है। जिसमें सड़क तो है लेकिन कीचड़ से भरा हुआ है। साथ ही जंगल होने के कारण कई जंगली जानवरों से भी सामना हो जाता है। जैसे-तैसे इन सबसे निकल गए तो फिर बीच रास्ते में नदी और नाले पड़ते हैं।

वन अमले ने पकड़ा रेत से भरा वाहन तो विवाद, धमकी देकर छुड़ाकर ले गए आरोपी

शहडोल। शहडोल जिले में अवैध रेत कारोबार से जुड़े लोगों के हौसले बढ़ते जा रहे हैं। सोहागपुर थाना क्षेत्र में कार्रवाई करने पहुंचे वन अमले के साथ कथित तौर पर विवाद करने और जब्त रेत से भरे वाहन को छुड़ाकर ले जाने का मामला सामने आया है। आरोप है कि इस दौरान वनकर्मियों को डंडे से पीटने की धमकी भी दी गई। घटना के बाद वन विभाग की ओर से पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई है। वन परिक्षेत्र अधिकारी विनायक कुमार गौतम की शिकायत के अनुसार, वन अमले को अवैध रूप से रेत परिवहन किए जाने की सूचना मिली थी। टीम कार्रवाई के लिए मौके पर पहुंची और रेत से भरे वाहन को पकड़ लिया। इसी दौरान छेंकलाल यादव, श्रीपत मिश्रा सहित कुछ अन्य लोग वहां पहुंच गए। आरोप है कि उन्होंने वनकर्मियों से विवाद करते हुए कार्रवाई का विरोध किया और बलपूर्वक वाहन छुड़ाकर ले गए। शिकायत में वन अमले को धमकाने का भी आरोप लगाया गया है। मामले को गंभीरता से लेते हुए सोहागपुर पुलिस ने छेंकलाल यादव, श्रीपत मिश्रा और 2-3 अज्ञात लोगों के खिलाफ शासकीय कार्य में बाधा डालने समेत अन्य धाराओं में प्रकरण दर्ज किया है। पुलिस अब नामजद और अज्ञात आरोपियों की तलाश कर रही है। वन विभाग की कार्रवाई के दौरान माफियाओं द्वारा टीम के साथ विवाद और दबाव बनाने की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं।

भोपाल-इंदौर हाईवे पर पहली बार बैरियर फ्री टोल प्लाजा दनदनाते निकलेंगे वाहन

सच संवाददाता || इंदौर

मध्य प्रदेश में यात्रियों को सुगम और बाधारहित यात्रा के लिए तकनीकी रूप से अपग्रेड करने देवास-भोपाल हाईवे के फंदा टोल प्लाजा पर बैरियर-फ्री टोलिंग व्यवस्था शुरू की गई है। पहली बार देवास भोपाल कॉरिडोर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया गया है। अब टोल प्लाजा पर वाहनों को बैरिकेड लगाकर ना तो रोका जा रहा है, ना ही वाहन चलकों को टोल प्लाजा से गुजरने के लिए अब लंबी लाइन में लगना पड़ रहा है। इससे यात्रियों का समय तो बचेगा ही, साथ ही धन की बचत और वाहनों के ट्रैफिक से मुक्ति मिलने की उम्मीद है।फंदा टोल प्लाजा पर चल रहे पायलट में फास्ट्रेक के साथ कैमरा आधारित वाहन पहचान तकनीक का उपयोग किया जा रहा है। इसके जरिए वाहन की पहचान और टोल लेन-देन की प्रक्रिया को स्वचालित बनाने की दिशा में काम किया जा रहा है। पायलट प्रोजेक्ट के तहत वाहनों को बिना रुके टोल क्षेत्र से गुजरने की सुविधा का परीक्षण किया जा रहा है। इससे न केवल यात्रियों की यात्रा अधिक सुविधाजनक हो सकती है, बल्कि बार-बार ब्रेक लगाने और वाहन को दोबारा गति देने से होने वाली ईंधन खपत को भी कम करने में मदद मिलेगी।

टोल प्लाजा पर वाहनों की आवाजाही अधिक सुचारु होने से पीक ऑवर्स में लगने वाली कतारों और अनावश्यक रुकावटों को कम करने में मदद मिलेगी। बैरियर फ्री टोल वसूली की तकनीक के विस्तार की संभावना के चलते जल्द ही भोपाल-देवास कॉरिडोर पर फंदा के अलावा अमलाहा और भौरासा टोल प्लाजा भी यह व्यवस्था लागू हो सकती है। इस पहल से भविष्य में टोल प्लाजा पर यात्रा के समय की कम करने, ईंधन की बचत करने और वाहनों की आवाजाही को अधिक सुगम बनाने में मदद मिलने की उम्मीद है।देवास-भोपाल कॉरिडोर प्राइवेट लिमिटेड के प्रोजेक्ट मैनेजर अजय मिश्रा बताते हैं संबंधित टोल प्लाजा पर बैरियर फ्री टोल वसली की नई व्यवस्था के तहत फास्टैग और कैमरे आधारित वाहनों की स्कैनिंग की तकनीक का उप्रयोग किया जा रहा है। इसमें फास्ट्रेक और कैमरा आधारित वाहन पहचान तकनीक का उपयोग किया जा रहा है, ताकि टोल लेन में वाहनों के रुकने और प्रतीक्षा समय को कम किया जा सके। पायलट प्रोजेक्ट के दौरान तकनीकी प्रक्रिया, वाहन पहचान और टोल लेन-देन के संचालन का आकलन किया जा रहा है।

मझगांय डैम के पानी में उतरे आदिवासी किसान

चिता बनाकर किया अनोखा विरोध गले में फंदा डाल जताई नाराजगी

सच संवाददाता || पन्ना

पन्ना जिले के अजयगढ़ थाना क्षेत्र में मझगांय सिंचाई परियोजना को लेकर आदिवासी किसानों का अनोखा विरोध सामने आया है। जय किसान पार्टी के बैनर तले बड़ी संख्या में ग्रामीण और प्रभावित किसान डैम के पानी के बीच पहुंचकर प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन के दौरान किसानों ने पानी के बीच सांकेतिक रूप से चिता बनाई। वहीं, कुछ प्रदर्शनकारियों ने गले में फंदा डालकर अपनी मांगों की ओर प्रशासन का ध्यान आकर्षित किया।

किसानों का कहना है कि उनकी जमीन मझगांय सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र में आ रही है, लेकिन उन्हें अब तक जमीन के मुताबिक उचित मुआवजा नहीं मिला है। किसानों ने आरोप लगाया कि परियोजना के कारण उनकी कृषि भूमि डूब क्षेत्र में जा रही है, जिससे उनके सामने रोजी-रोटी और भविष्य का संकट खड़ा हो गया है।

अजयगढ़ क्षेत्र में मझगांय सिंचाई परियोजना के निर्माण को लेकर डूब क्षेत्र में आने वाले किसानों और ग्रामीणों में नाराजगी है। प्रभावित किसानों का आरोप है कि शासन-प्रशासन की ओर से मुआवजे की प्रक्रिया की जा रही है, लेकिन कई परिवारों को उनकी जमीन के मुताबिक उचित मुआवजा नहीं मिल पा रहा है। प्रदर्शनकारियों का यह भी आरोप है कि कई पात्र हितग्राहियों के नाम मुआवजा सूची में शामिल ही नहीं किए गए हैं। किसानों का कहना है कि परियोजना से वास्तव में प्रभावित होने वाले परिवारों का निष्पक्ष सर्वे कराया जाए और उनके नाम मुआवजा सूची में शामिल किए जाएं, ताकि उन्हें उनका अधिकार मिल सके।

ग्रामीणों की मुख्य मांग है कि डूब क्षेत्र में आने वाली जमीन का निष्पक्ष सर्वे कराया जाए। इसके साथ ही प्रभावित किसानों को उनकी जमीन के मुताबिक उचित और न्यायसंगत मुआवजा दिया जाए। जिन पात्र परिवारों के नाम अभी तक मुआवजा सूची में शामिल नहीं किए गए हैं, उन्हें भी तत्काल सूची में जोड़े जाने की मांग की जा रही है।

किसानों का कहना है कि उन्होंने अपनी मांगों को लेकर कई बार प्रशासन के सामने अपनी बात रखी, लेकिन समस्याओं का उचित समाधान नहीं हुआ। इसके बाद उन्हें आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ा। इसी क्रम में किसानों ने पानी के बीच चिता बनाकर और गले में फंदा डालकर सांकेतिक विरोध किया।

ग्वालियर एयरफोर्स स्टेशन परिसर में चोरी

ग्वालियर। ग्वालियर के अति-संवेदनशील एयरफोर्स स्टेशन महाराजपुरा की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। एयरफोर्स कैंपस से विमानों में उपयोग आने वाले हाई-वैल्यू एवियोनिक्स स्क्रैप की चोरी का मामला सामने आया है। चोरों ने सुरक्षा एजेंसियों को चकमा देने के लिए कचरा उठाने वाले ट्रैक्टर का इस्तेमाल किया और कथित तौर पर कचरे के नीचे कीमती स्क्रैप छिपाकर उसे एयरफोर्स स्टेशन के मुख्य गेट से बाहर निकाल दिया। घटना 9 सितंबर की शाम करीब 4 से 5 बजे के बीच की बताई जा रही है। चोरी किए गए स्क्रैप की कीमत 50 हजार रुपये से अधिक बताई गई है। मामले का खुलासा तब हुआ, जब एयरफोर्स स्टेशन की निगरानी कर रहे अधिकारियों को अलग-अलग स्थानों पर रखे स्क्रैप की मात्रा कम नजर आई। इसके बाद प्राथमिक स्तर पर जांच की गई और चोरी की जानकारी सामने आई। एयरफोर्स स्टेशन के सुरक्षा अनुभाग की ओर से महाराजपुरा थाना पुलिस को लिखित शिकायत दी गई। शिकायत के आधार पर पुलिस ने शनिवार, 12 सितंबर को चोरी और आपराधिक साजिश का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने तीन नामजद आरोपियों को हिरासत में लिया है और उनसे पूछताछ की जा रही है।

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट सांसद महेश केवट को भेजा गया नोटिस सर्व हुआ माना जाए

मीनाक्षी नटराजन केस, रजनीश अग्रवाल का नहीं मिला पता, महेश केवट ने नोटिस लेने से किया मना

सच संवाददाता || जबलपुर

राज्यसभा सदस्य का नामांकन निरस्त किये जाने को चुनौती देते हुए कांग्रेस नेत्री मीनाक्षी नटराजन की तरफ से दायर याचिका पर शनिवार को सुनवाई हुई। इस मामले में हाईकोर्ट ने भाजपा के नवनिर्वाचित 3 राज्यसभा सांसद सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था।

याचिका पर हुई सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट जस्टिस बी पी शर्मा की एकलपीठ को बताया गया कि राज्यसभा सांसद रजनीश अग्रवाल का पता नहीं मिलने के कारण नोटिस सर्व नहीं हो पाया। इसके अलावा राज्यसभा सांसद महेश केवट ने नोटिस स्वीकार करने से इंकार कर दिया।हाईकोर्ट में याचिका की सुनवाई के दौरान एकलपीठ को बताया गया कि सांसद तरुण चुघ को भेजी गयी याचिका की कॉपी पढ़ने लायक नहीं है। सांसद रजनीश अग्रवाल का पता नहीं मिलने के कारण नोटिस सर्व नहीं हो पाया है। सांसद महेश केवट ने नोटिस स्वीकार करने से इंकार कर दिया। याचिकाकर्ता की तरफ से बताया गया कि सांसद रजनीश अग्रवाल के द्वारा चुनाव आयोग में दिये गये फार्म के पते पर नोटिस सर्व किया गया था। इसके अलावा केन्द्रीय चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त, रिटर्निंग अधिकारी, प्रमुख सचिव मध्य प्रदेश विधान सभा और मुख्य निर्वाचन अधिकारी राज्य चुनाव आयोग की तरफ से याचिका से उनका नाम विलोपित किये जाने की मांग करते हुए आवेदन पेश किया।हाईकोर्ट जस्टिस बी पी शर्मा की एकलपीठ ने अपने आदेश में कहा, सांसद तरुण चुघ को पिटिशन की कॉपी और दस्तावेज ई-मेल के माध्यम से भेजने के निर्देष याचिकाकर्ता के अधिवक्ता को दिये हैं। सांसद रजनीश अग्रवाल को आरएडी मोड (रजिस्टर्ड पावती सहित) से नोटिस भेजे जाएं। सांसद महेश केवट को भेजा गया नोटिस सर्व हुआ माना जाए और उन्हें जवाब दाखिल करने के लिए एक अवसर और प्रदान किया जाता है। नाम हटाने के लिए दायर आवेदन पर याचिकाकर्ता अपना जवाब पेश करें।

कांग्रेस नेत्री मीनाक्षी नटराजन की तरफ से दायर की गई चुनाव याचिका में कहा गया था कि तेलंगाना की एक अदालत में महिला द्वारा दायर व्यक्तिगत परिवाद में उन्हें प्रतिवादी बनाया था। प्रतिवादी बनाए जाने के कारण न्यायालय ने उनके पक्ष के लिए उन्हें नोटिस जारी किया था। उनके खिलाफ कोई आपराधिक केस दर्ज या विचाराधीन नहीं था। उनके नामांकन पर आपत्ति प्रस्तुत किये जाने पर रिटर्निंग ऑफिसर ने नियमों के विपरीत जल्दबाजी में न्यायालय में लंबित प्रकरण की जानकारी छुपाने के आधार पर उनका नामांकन निरस्त कर दिया।उन्होंने सुनवाई के दौरान रिटर्निंग अधिकारी को बताया था कि परिवाद में उनके खिलाफ कोई आरोप नहीं है, सिर्फ औपचारिक तौर पर उन्हे अनावेदक बनाया गया है। रिटर्निंग ऑफिसर के द्वारा उनका नामांकन नियम विरुद्ध तरीके से निरस्त किया गया है। जिसके कारण यह याचिका दायर की गई है। याचिका में मध्य प्रदेश से निर्वाचित राज्यसभा सदस्य तरुण चुघ, रजनीश कुमार अग्रवाल, महेश केवट, केन्द्रीय चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त, रिटर्निंग अधिकारी, प्रमुख सचिव मध्य प्रदेश विधान सभा तथा मुख्य निर्वाचन अधिकारी राज्य चुनाव आयोग को अनावेदक बनाया गया है।